

यूएस' रो बनाम वेड केस 1973

प्रलिस के लयि: यूएस' रो बनाम वेड केस 1973, भारत में गर्भपात संबंधी कानून

मेन्स के लयि: गर्भपात, सरकारी नीतियों और हस्तक्षेप, महिलाओं से संबंधित मुद्दों, लयि के संबंध में बहस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राजनीतिक पत्रकारिता कंपनी **पोलिटिको** द्वारा दी गई एक जानकारी से पता चला है कि अमेरिकी **सर्वोच्च न्यायालय** ने वर्ष 1973 के ऐतिहासिक फैसले **रो बनाम वेड, 1973** को पलटने का नरिणय लया है, जसिने गर्भपात को **संवैधानिक अधिकार** बना दया था ।

रो बनाम वेड फैसला क्या था?

- वर्ष 1973 में **रो बनाम वेड** के ऐतिहासिक फैसले में संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बना दया, जो दुनया भर में गर्भपात कानूनों के लयि एक बेंचमार्क स्थापति हो गया ।
- इस मामले में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने कई राज्यों में **गर्भपात को अवैध बनाने वाले कानूनों को रद्द कर दया** और फैसला सुनाया कि **गर्भपात को भ्रूण की व्यवहार्यता के बढु तक अनुमति** दी जाएगी, यानी वह समय जसिके बाद भ्रूण गर्भ के बाहर जीवति रह सकता है ।
 - रो के फैसले के समय भ्रूण की व्यवहार्यता लगभग **28 सप्ताह (7 महीने)** थी, अब वरिषज्ज इस बात से सहमत हैं कि दिवाइयों की प्रगतने इस **सीमा को 23 या 24 सप्ताह (6 महीने या थोडा कम)** तक ला दया है ।
- भ्रूण की व्यवहार्यता को अक्सर उस बढु के रूप में देखा जाता है जसि पर **महिला के अधिकारों को अजन्मे भ्रूण के अधिकारों से अलग कया** जा सकता है ।
- दुनया भर में गर्भपात कानून इस समय-सीमा पर भरोसा करते हैं लेकनि गर्भपात का वरिध करने वालों का तर्क है कि यह **एकनमानी समय-सीमा है जसि कानूनों के माध्यम से अदालत ने अपनाया है** ।

गर्भपात संबंधी बहस क्या है?

- गर्भपात पर बहस प्रेरति गर्भपात की नैतिक, कानूनी और धार्मिक स्थतिको लेकर चल रही है ।
- कई पश्चिमी देशों में बहस में शामिल पक्ष स्व-वर्णति **'प्रो-चॉइस'** और **'प्रो-लाइफ'** एक आंदोलन है ।
 - प्रो-चॉइस** गर्भावस्था को समाप्त करने के लयि महिला की पसंद पर ज़ोर देती है ।
 - इसके वपिरीत **प्रो-लाइफ** स्थतिमाँ और भ्रूण दोनों की मानवता पर ज़ोर देती है, इसमें यह तर्क दया जाता है कि भ्रूण कानूनी संरक्षण के योग्य मानवीय व्यक्ता है ।
- जनता की राय को प्रभावति करने तथा अपनी स्थतिके संदर्भ मे कानूनी समर्थन प्राप्त करने के लयि **प्रत्येक आंदोलन के अलग-अलग परिणाम** हैं ।
- बहुत से लोग मानते हैं कि गर्भपात अनवर्य रूप **सेमानवीय व्यक्तातिव की शुरुआत, भ्रूण के अधिकारों और शारीरिक अखंडता से संबंधित एक नैतिक मुद्दा** है ।

वर्तमान मामला क्या है?

- वर्तमान मामला गर्भपात पर **मसिसिपी कानून को चुनौती** देने से संबंधित है ।
- वर्ष 2018 में मसिसिपी राज्य ने 1973 के फैसले को सीधी चुनौती देते हुए 15 सप्ताह के बाद अधिकांश गर्भपात पर प्रतबंध लगा दया ।
- वर्ष 2019 में मसिसिपी में "हार्टबीट" नामक गर्भपात कानून पारति कया गया था, जो कएक और भी अधिकि प्रतबंधात्मक उपाय था, इसने भ्रूण की हृदय गतविधिका पता चलने के बाद (लगभग छह सप्ताह) अधिकांश गर्भपात पर प्रतबंध लगा दया ।
- "हार्टबीट" में कहा गया है कि भ्रूण के हृदय की धड़कन का पता चलने के बाद गर्भपात करने वाले चकित्सकों के मेडिकल लाइसेंस रद्द हो सकते हैं ।
 - कानून में बलात्कार या अनाचार के कारण गर्भधारण के लयि कोई अपवाद मौजूद नहीं है ।
- इस कानून को भी एक ज़िला जज ने खारज़ि कर दया था और फरवरी 2020 में न्यू ऑरलियन्स में 5वीं **'सर्कटि कोर्ट ऑफ अपीलस'** ने इस फैसले पर सहमति जताई थी ।

नरिणय का प्रभाव:

- चूँकि अमेरिका में गर्भपात के अधिकार की रक्षा करने वाला कोई संघीय कानून नहीं है, इसलिये 'रो' को पलटने से गर्भपात कानून पूरी तरह से राज्यों पर नरिभर हो जाएगा ।
- संक्षेप में 'रो बनाम वेड' की जाँच और संतुलन की अनदेखी तथा व्यक्तिगत एजेंसी को अक्षम करने से मामला अब महिलाओं के अधिकारों के प्रतमान के भीतर प्रतस्थापति नहीं किया जाएगा ।
- यह मानव अधिकारों के बड़े ढाँचे को भी प्रभावित कर सकता है, यह गरीबों एवं हाशिये पर स्थिति लोगों को और दूर कर देगा ।

भारत में गर्भपात संबंधी कानून:

- भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 312 के तहत गर्भपात एक अपराध है ।
 - हालाँकि मेडिकल टर्मनिशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 (MTP) और इसका संशोधन केवल अपराधीकरण को अपवाद की स्थिति प्रदान करता है ।
- MTP अधिनियम, 1971 गर्भावस्था के 20 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति देता है ।
- लेकिन केवल विशेष श्रेणी की गर्भवती महिलाओं जैसे कि बलात्कार या अनाचार से प्रभावित के लिये (वह भी दो पंजीकृत डॉक्टरों की मंजूरी के साथ) वर्ष 2021 में एक संशोधन के माध्यम से गर्भपात की सीमा को बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया था ।
- भ्रूण की विकलांगता के मामले में गर्भपात की कोई समय-सीमा नहीं है, लेकिन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा स्थापित विशेषज्ञ डॉक्टरों के एक मेडिकल बोर्ड द्वारा इसकी अनुमति दी जाती है ।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/us-roe-v-wade-case-1973>

